[श्री शिव प्रसाद चनपूरिया]

अधिकार दिया जाए कि वह हर महीने कम से कम एक बार जाकर निरीक्षण करे। और बता कर निरीक्षण न करें। मैं बिना बताए हुए वहां गया था, इसलिए सब स्थिति मुझे देखने को मिल गई।

यहां तक विडम्बना है कि जो मां-बाप अपने बच्चों को वहां रखे हैं, वह मेरे पास आये। उन्होंने कहा कि हमारी तो यह इच्छा होती है कि हम अपने बच्चे को इस विद्यालय से निकाल कर सामान्य विद्यालय में भर्ती कर दें। हमारे बालक का जीवन यहां सुरक्षित नहीं है, न उसका स्वास्थ्य सुरक्षित है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिस एक छात्र पर हम नौ हजार रुपये से अधिक खर्च करें, वहां का बालक, वहां का छात्र आज इस स्थिति में रहे कि न उसको खाने को ठीक मिल सके, न रहने को ठीक मिल सके, न पीने का पानी मिल सके।

उनको शुद्ध पानी नहीं मिलता। उनके लिए टैंकर से पानी आता है। फिर उसमें एक रबर की पाईप रहती है, और उस सटक से फिर वह टोंटी से मुंह लगा कर वह पानी पीते हैं। आप कल्पना कीजिए, इस तरह से अगर हम छोटे बच्चों के साथ, जिन्हें हमें इस देश का सपूत बनाना है, मगर उनके जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते रहेंगे और यहां बड़ी-बड़ी बहस करें कि नवोदय विद्यालय में इतने करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। अभी आप 261 नवोदय विद्यालय नहीं संभाल सके अच्छी तरह से, तो हर जिले में नवोदय विद्यालय की क्या जरूरत होगी। यह कल्पना की बात है।

तो मेरा यह आग्रह है आपके माध्यम से और इस महान सदन के माध्यम से इस शासन से कि कम से कम वह मानव संसाधन विभाग को यह हिदायत दे कि हर नवोदय विद्यालय की अच्छी तरह से देखरेख हो। बच्चों के स्वास्थ्य की पूर्ण से जांच करके, उनके लिए स्वास्थ्य भोजन की व्यवस्था करें, स्वास्थ्यमय पानी की व्यवस्था शीघ्र करें और उनके रहने की व्यवस्था ठीक की जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपसभाध्यक्ष महोदया जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

Need to provide Royalty to Himachal Pradesh on power Generation through Hydro-Electric Projects.

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 5 मार्च 1990 को कार्यभार संभाला था। उस समय सरकार का खजाना खाली था, 290 करोड़ का घाटा और 127 करोड़ की देनदारियां थीं। ऐसी गंभीर स्थिति में ऐसे आर्थिक संकट के समय में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और उसके पश्चात् अपनी योजनाओं का रूप बदला है और सरकार इस चीज के लिए प्रयत्नशील है कि हिमाचल प्रदेश स्वावलम्बी बन सके और हिमाचल प्रदेश आत्म-निर्भर बन सके।

हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से एक सम्पन्न प्रदेश है परन्तु वहां की जनता गरीब है और सरकार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। खेद का विषय है कि पिछली सरकार लगभग चार दशक तक केन्द्र की बैसाखियों का सहारा लेकर चलती रही, जिसके फलस्वरूप आज हिमाचल प्रदेश की यह स्थिति बनी है कि सरकार हिमाचल प्रदेश को स्वावलम्बी बनाना चाहती है, आत्म-निर्भर बनाना चाहती है। उसके लिए हिमाचल की सरकार ने तीन-सूत्री कार्यक्रम बनाया है।

1. सब प्रकार की फिजूलखर्ची को सरकार रोकना चाहती है। उस पर अंकुश लगाना चाहती है।
2. प्रदेश में नये आर्थिक साधन जुटाना चाहती है, और

3. दिल्ली में बैठी हुई सरकार से अपना अधिकार लेना चाहती है ।

जहां तक नं० 1 सूत्र का संबंध है, इस चीज के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं कि आज फिजूल-खर्ची पर अंकुश लगा कर हिमाचल प्रदेश की छोटी सी उस सरकार ने 80 करोड़ की बचत करके दिखा दी है जिसके लिए प्लानिंग कमीशन ने भी उसकी प्रशंसा की है ।

जहां तक नये आर्थिक साधन जुटाने का संबंध है, यह बात सर्व-विदित है कि हिमाचल प्रदेश अकेला ऐसा प्रदेश है। जो 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है खेद का विषय है कि पिछली सरकार अपने शासनकाल में केवल मात्र 3,370 मेगावाट बिजली ही पैदा कर सका । आज हिमाचल की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि यह जो 20,000 मेगावाट की क्षमता है, 10,000 क्षमता का दोहन निजी क्षेत्र में किया जायगा और दस हजार मेगावाट का दोहन हिमाचल सरकार अपने तौर पर करेगी इस प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय लेकर हिमाचल सरकार चली है लेकिन जहां तक केन्द्र से अपना अधिकार लेने के संबंध में है उपसभाध्यक्ष महोदया आप इस बात को भली भांति जानती हैं कि आज जो प्रदेश कोयला पैदा करता है, जो तेल पैदा करता है, जो गैस पैदा करता है, हर प्रांत रायल्टी लेने का अधिकार रखता है । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहूंगा कि कौन से कारण हैं कि इस रायल्टी के अधिकार से हिमाचल प्रदेश को वंचित रखा गया है ? जब हिमाचल प्रदेश की धरती है, हिमाचल प्रदेश का पानी है और पानी पर आधारित परियोजनाओं से जो बिजली पैदा होती है उसमें जो देय राशि हिमाचल सरकार को भारत सरकार की ओर से बनती है वह लगभग 200 करोड़ रु० प्रतिवर्ष की बनती है। सैद्धांतिक रूप में भारत सरकार ने यह स्वीकार किया है सितम्बर, 1990 के बाद जो भी योजनाएं निर्मित होंगी उन पर तो वह 12 प्रतिशत बिजली मुफ्त रायल्टी के रूप में हिमाचल सरकार को देने को तैयार है, लेकिन हम इसी बात को लेकर मानने वाले नहीं है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि जैसे और प्रांतों को रायल्टी मिलती है इसी प्रकार जो हिमाचल की धरती और हिमाचल के पानी से बिजली पैदा हो उस पर से जो 200 करोड़ रुपये वार्षिक का हमारा अधिकार है वह हिमाचल सरकार को अविलम्ब दिया जाए । आज हम हिमाचल निवासी भारत सरकार से कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं । मैं आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर यह अधिकार हमको नहीं दिया गया तो इसके लिए हिमाचल की जनता बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार है । मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जो यह न्यायोचित मांग हिमाचल की सरकार ने भारत सरकार के समक्ष रखी है उसे सरकार शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे यह एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का यहां अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE (Gujarat) : I associate myself with this.

हिमाचल को यह देना चाहिए । जहां-जहां कुदरती सम्पत्ति निकलती है उनको उसका हिस्सा देना चाहिए रायल्टी देनी चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आपका एसोसिएशन रेकार्ड कर लिया जाएगा श्री मोहम्मद अमीन ।

—

Suspension of Purchase of Raw Jute by Jute Corporation of India

श्री मोहम्मद अमीन : (पश्चिमी बंगाल) मोहतरमा, मैं आपके जरिए इस सरकार की तवज्जह इस बात की तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि जूट कार्पोरेशन आफ़ इंडिया ने कच्चे पाट की खरीदारी 15 दिनों से बन्द कर दी है । मेरे पास आज एक टेलीग्राम कलकत्ता से आया है । उसमें यह लिखा हुआ है कि 15 दिनों से जे० सी० आई० के पास कोई फ़ंड नहीं है, इसलिए उसके कई हजार कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं । एक तो यह सरकार का नुक्सान हो रहा है, दूसरा यह है कि जे०सी०आई० जब कच्चे पाट की खरीदारी बन्द कर देती है तो पाट का दाम गिर जाता है और दाम गिर जाने से किसानों को नुक्सान पहुंचता है । फिर जे० सी० आई० के पास अगर पाट नहीं रहेगा तो जो सरकारी जूट मिलें हैं उनको कच्चे पाट की सप्लाई रुक जाएगी, उनके प्रोडक्शन का नुक्सान हो जाएगा । इसलिए यह तीन किस्म का नुक्सान एक ही साथ हो रहा है और यह बहुत भारी नुक्सान है ।

इसलिए मैं आपके जरिए सरकार से और मिनिस्ट्री आफ़ टेक्सटाइल से यह मांग करता हूं कि फ़ौरन वह जे०सी०आई० को फंड मुहैया करे, ताकि कच्चे पाट की खरीदारी फ़िर शुरू हो सके ।

†[شری محمد امین: "پشچمی بنگال" محترمہ میں آپ کے ذریعہ اس سرکار کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جوٹ کارپوریشن آف انڈیا نے کچے پاٹ کی خریداری ۱۵ دنوں سے بند کر دی ہے۔ میرے پاس آج ایک ٹیلیگرام کلکتہ سے آیا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ۱۵ دنوں سے جے۔ سی۔ آئی۔ کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے اس لیے اس کے کئی ہزار کرمچاری ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ایک تو یہ سرکار کا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جے۔ سی۔ آئی۔ جب کچے پاٹ کی خریداری بند کر دیتی ہے تو پاٹ کا دام گر جاتا ہے اور دام گر جانے سے کسانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ پھر جے۔ سی۔ آئی کے پاس اگر پاٹ نہیں رہے گا تو جو سرکاری جوٹ ملے ہیں تو انکو کچے پاٹ کی سپلائی روک دی جائے گی۔ انکے پروڈکشن کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تین قسم کا نقصان ایک ہی ساتھ ہو رہا ہے اور یہ بہت بھاری نقصان ہے۔

اس لیے میں آپ کے ذریعہ سرکار سے اور منسٹری آف ٹیکسٹائل سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ فوراً وہ جے۔ سی۔ آئی۔ کے فنڈ مہیا کریں تاکہ کچے پاٹ کی خریداری پھر شروع ہو سکے۔

"ختم شد"]

†[ ] Transliteration in Arabic Script